of machines in phase I and II has been completed. Tender formalities have also been completed in respect of some other demolition and disposal works, rehabilitation and construction of miscellaneous buildings and sheds, etc.

(c) and (d) It was intended to implement this scheme with the Dutch financial and technical assistance. Implementation of the project has got delayed, because it has taken some time to obtain confirmation from the Dutch Authorities in regard to their financial commitment to this project.

(e) With the Dutch financial and technical assistance, it is now proposed to undertake the various activities relating to execution of this project expeditiously.

High-Speed Ferry Service between Panjim and Bombay

2258. MISS SAROJ KHAPARDE: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether a high-speed ferry service is likely to become operational between Panjim and Bombay around November this year; and

(b) if so, the details thereof including the fares to be charged from the passengers?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI JAGDISH TYTLER): (a) and (b) The government has recently permitted M/s. Damania Airways Limited (Shipping Division) for acquisition of a new built Catamaran to be operated between Panjim and Bombay. As per indication given by the company, the service on this route is likely to be started in November, 1994. The likely passenger fare to be charged by the company is Rs. 700/- for lower deck and Rs 1,200/- for upper deck.

Transfer of DTC to Delhi Government

2259. SHRI O. P. KOHLI:

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA:

Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether there is any proposal to transfer the DTC with its assets minus accumulated losses to the Government of Delhi;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI JAGDISH TYTLER): (a) At present, the Government have no such proposal.

(b) Does not arise.

(c) The Government of National Capital Territory of Delhi is unlikely to accept the transfer of DTC in view of huge losses and financial outstanding liabilities of DTC, which the Central Government, presently is not in a position to write-off.

पथकर तथा चुंगी संबंधी ज्योति बसु समिति

2260. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :**
श्री दिग्विजय सिंह :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पथकर तथा चुंगी को समाप्त करने के संबंध में ज्योति बसु समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति ने अपने प्रतिवेदन में क्या सिफारिशें की हैं तथा क्या सरकार इस प्रतिवेदन की सिफारिशों को लागू करना चाहेगी क्योंकि कर वसूल करना राज्यों का संवैधानिक अधिकार है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) जी, हां। समिति ने यह अभिमत व्यक्त किया है कि चुंगी को संविधान की राज्य सूची की प्रविष्टि-52 द्वारा संरक्षण प्राप्त है और इसे समाप्त करने का प्रश्न ही नहीं है। समिति द्वारा अभिव्यक्त संवैधानिक उपबंधों को देखते हुये सरकार की ओर से और कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

व्यापारिक जहाजरानी कानूनों में संशोधन

2251. **श्री सोमपाल :**
श्री शारदा महन्ती :

क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौंतीस वर्ष पुराने व्यापारिक जहाजरानी कानूनों में संशोधन करने संबंधी कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा संशोधन के प्रयोजन सहित इनका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उक्त संशोधनों को कब तक प्रभावी बनाये जाने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) जी, हां। वाणिज्य नौवहन अधिनियम, 1958 में संशोधन करने का मुख्य कारण भारत द्वारा अनुसमर्पित अन्तर्राष्ट्रीय कंवेशनों, समझौतों और प्रोटोकोलों के विभिन्न प्रावधानों को लागू करना तथा नौवहन क्षेत्र के विकास से संबंधित महत्वपूर्ण पहलुओं संबंधी उपायों को शामिल करना है। चूंकि यह प्रस्ताव अभी जांच के प्रारंभिक चरण में है इसलिये यह बता पाना संभव नहीं है कि ये संशोधन कब तक कर दिये जायेंगे।

मध्य प्रदेश को पर्यटक स्थलों के लिए सड़कों के निर्माण हेतु विशेष अनुदान

2262. **श्री राघवजी** : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने पर्यटन स्थलों, पुरातत्व महत्व के स्थलों तथा अन्य रमणीय स्थलों को सुलभ बनाने के लिये सड़कों के निर्माण हेतु विशेष अनुदान की मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उस पर केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार अपनी ओर से पर्यटन को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से ऐसी सड़कों के निर्माण हेतु राज्य सरकार को अनुदान देने के लिये कोई नीति बनायेगी, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में अन्तर्राष्ट्रीय अथवा आर्थिक महत्व की राज्यीय सड़कों के लिये केन्द्र द्वारा सहायता प्रदत्त कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्त पोषण हेतु पर्यटनपरक सड़क स्कीम के रूप में 42.84 करोड़ रुपये की लागत से 16 (सोलह) प्रस्ताव पेश किये हैं। आठवीं योजना की केन्द्रीय क्षेत्र में सड़कों के कार्यक्रम के अन्तर्गत सीमित निधियों के आबंटन के कारण मध्य प्रदेश सहित किसी भी राज्य में कोई नई परियोजना शुरू कर पाना इस समय संभव नहीं है।

Malayasian firm to build expressways in India

2263. SHRI SANJAY DALMIA: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a Malayasian firm has offered to build expressways in India with plans to invest upto